

संस्कृति पर आधारित व्यवस्था को समूल नाश करने के लिए अर्जक संसद के समान सांठन की थायाना 1 जून 1968 को की। इसके माध्यम से देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव का विधुल नै फेका, जिससे समाज में फैले छत्र-बाद, पुण्डितू जाति-आदि व्यवस्था, धनश्याम चौधरी के प्रमोद चौधरी, माराधम चौधरी, अजय चौधरी, कुशार्क चौधरी, विद्यासागर चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, आर. श्याम नारायण चौधरी, मंशाराम चौधरी, भरतराम चौधरी, अश्या रंजन आदि उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेलेट फिलिपा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 25 अगस्त 2025 सोमवार

सम्पादकीय

उपराष्ट्रपति चुनाव

उपराष्ट्रपति पद के लिए अब दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले इण्डिया ब्लॉक ने सुश्रीम कोटं के रिटायर्ड जज बी. सुरेशन रेड्डी को उतारा है। संख्या बल में एनडीए यानी सत्ता पक्ष का पतनड़ा भले भारी सही, लेकिन यह लड़ाई आंकड़ों से ज्यादा प्रतीकालमक है। विपक्ष ने एक मजबूत कोडिडेट उत्तराकर उम्मीद देने का प्रयास किया है कि वह किसी मोर्चे पर सरकार को फ्री हैंड नहीं देने जा रही।

राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जबकि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से। दोनों चेहरों का दक्षिण भारत से होना संयोग नहीं हो सकता और इसी वजह से यह चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। भाजपा के लिए दक्षिण अब भी मुश्किल जगह है, जबकि विपक्ष के लिए ऐसा मैदान, जहां उसने मजबूत चुनौती पेश की है। उपराष्ट्रपति चुनाव उसी सिपायी लड़ाई का विस्तारित रूप है। जिस तरह से टीडीपी ने राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया है, उसका असर दिखने भी लगा है। अगर सी फ्रीस्टी वोटिंग 394 वोट चाहिए होंगे। छवः के पास 422 का संख्याबल है। हालांकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और सदस्य पार्टी विप से नहीं कंे।

होते। सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए यह मौके के साथ चुनौती भी है। दोनों तरफ से अपने समर्थन का दावरा बढ़ाने की कोशिश होगी। खासतौर पर दक्षिण से आने वाले क्षेत्रीय दलों पर नजरें होगी।

उपराष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता। इसकी गरिमा को देखते हुए अगर सर्वसम्मति से किसी को चुना जाता, तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि अभी का राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखती। देश में पिछले कुछ बरसों से जिस तरह का माहौल है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ज्यादातर मौकों पर दो विपरीत दिशाएं पर नजर आए हैं। जिन मामलों में सदन में सहमति की मांग थी, वहां भी सहमति नहीं दिखी, तो यह चुनाव तय ही था। हालांकि लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति पद के इर्द-गिर्द हाल में बहुत हलचल देखने को मिली है। जगदीप धनखड़ जिन परिस्थितियों में आए जैसे गए, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि यह चुनाव बेहतर माहौल में और इस पद के सम्मान को देखते हुए उसके हिसाब से लड़ा जाएगा। जीत किसी भी हो, उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को आगे ले जाने की अहम जिम्मेदारी होगी।

बीच बहस में आवारा कुत्ते

सड़कों-गलियों में खुला घूमने वाले कुत्ते पर उच्चतम न्यायालय का आया ताजा निर्देश विवेकसम्मत और तार्किक है। रिस्कबेह अदालत ने पशु प्रेमियों की संवेदनाओं का खयाल रखा है, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जान सुख्खा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी नागरिक सड़क पर कहीं भी कुत्ते को खाना नहीं खिलाएगा। दरअसल, राजध्ानी में कुत्ते को काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे संज्ञान में लेकर अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द सड़कों से हटा कर आश्रय स्थल बेजान का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले को लेकर व्यापक स्तर पर चिंता जाहिर की गई कि क्या आवारा कुत्ते के प्रति थोड़ा नरम नहीं हुआ जा सकता है। मगर सवाल यह है कि इस पूरी समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर संभवित महकूमों की ओर से पशु जन्म नियंत्रण नियमों को गंभीरता से लागू किया गया होता, तो न कुत्ते की संख्या बढती और न ही सड़क सड़कों से हटाने की नीवत आती। अब अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा है कि हटाए गए कुत्ते का बंध्याकरण हो, टीकाकरण किया जाए और उन्हें उन्हीं क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें हटाय़ा गया था। हालांकि यह निर्देश आक्रामक व्यवहार वाले और संक्रमण के संदेह वाले कुत्ते पर लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि हर सभ्यता में कुत्ते मनुष्य के साथ रहे हैं। वे इंसानों के अच्छे साथी साबित हुए। संवेदना के स्तर पर परस्पर जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। कुत्ते आज लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। मगर अब समय आ गया है कि हम उन कारणों की भी पड़ताल करें, जिनकी वजह से कुत्ते का व्यवहार आक्रामक हुआ। कई राज्यों में इनकी बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। अगर संबंधित निकायों ने ध्यान दिया होता, तो अदालत सख्त कदम नहीं उठाती। स्थानीय उसका कनहा सही है कि यह समय समस्या ख्यालीय अधिकारियों की निष्क्रियता का नतीजा है। कुत्ते के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कहीं भी उन्हें खाना खिलाने की आदत हमें बदलनी होगी। इसीलिए ताकती की गई है कि इसके लिए खास जगह निर्धारित हो। इसे गंभीरता से लेने के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शीर्ष अदालत का निर्देश व्यापक और सफ़ाई है।

—अभिनव आकाश—

‘यें अकेला ही चला था जानिये—ए—मजिल मगर, लोग साथ आते मगर और कारवाँ बनाता गया’ मरुहम सुलतानपुरी की ये लाइनें मरुहम राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया है जब महात्मा गांधी दिसंबर 1914 के अंत में अवतरित होती है और उसके बाद से देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। इसीलिए लोगों के कब्र लगने वाली कांग्रेस पार्टी एक मांस आर्गनाइजेशन में बदल जाती है। जवाहर लाल नेहरू ने गांधी जी का जिक्र करते हुए इसमें बताया है कि गांधी जी ने सबसे बड़ा बदलाव जो भारतीय राजनीति में किया वो ये था कि उन्होंने लोगों के मन में जो खींच था। अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर जो डर था। गांधी ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर और लोगों के मानस में एक बड़ा बदलाव किया। अंग्रेजों के डर को खत्म कर दिया। उन्होंने लोगों को मुसंद बना दिया। अमय मालव जिसको मय नहीं है। जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने देश की संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बर्चा के दौरान अमय मुद्रा का बार बार जिक्र किया। शिव की तस्वीर में और कांग्रेस का चुनाव चिह्न अमय मुद्रा है और ये निखर रहने की बात कहते हैं। इसी दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुश्मन करना भी एक तरह की अमय मुद्रा है। वैसे तो देश में गौतमबुद्ध, शंकराचार्य, गुरुनानक से लेकर महात्मा गांधी और विनोबा भावे तक की पदयात्रा का अपना स्वरूपीम इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जब चला करते थे तो लोग जुड़ते चले जाते थे। वो कारवां बने बड़ा बड़ा करता था कि परिवर्तन की दिशा इस देश को आजादी के लेगा।

इससे इतर राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी पदयात्रा निकाली गई। यात्राएं इस देश की भीतर बहुत हुई हैं और हर यात्रा का कोई न कोई प्रतिकूल राजनीतिक दल या नेता के भीतर जरूर आया है। देश में अब तक कई हिंसासी यात्राएं हुई हैं, उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लोगों ने उनसे संवाद बनाया। उनके अपने सरोकार स्थिति ने सत्ता तक भी पहुंचाया है। आजादी की लड़ाई से आजादी के बाद तक विभिन्न तरीकों की लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कहीं न कहीं रांज लाती रिली है। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। अब राहुल गांधी वोट चोरी के सवाल को खड़ा करके बिहार के सारसाराने से निकलें हैं। 17 अगस्त शुक्र हुई यह यात्रा 16 दिनों में बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल इस दौरान 1300 किमी की दूरी तय करेंगे। राहुल की वोट अधिकार यात्रा उनकी अब तक की पांचवी बड़ी यात्रा होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। बर्फ और ठंड में टी शर्ट में उनका खड़े होना एक बचन बन गई थी। उसका बाद उन्होंने गिफ्टपुर से लेकर मुसंद तक और उसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में दिखा। कांग्रेस की सीटें बढ़ीं। बीजेपी की सीटें कम हुईं। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए शाब्द सबसे बड़ी अभिप्रेक्षा शूरी की राहों है। पहले की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा अंधा नहीं थी। न कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठ था। लोगों को लग रहा था कि राहुल कुछ नहीं कर रहे हैं तो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन दोनों यात्राओं



से राहुल गांधी की छवि बदली। कांग्रेस और उससे भी कहीं ज्यादा उनके सहयोगियों को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में नतीजा भी नजर आया। पिछले दिनों नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। राहुल गांधी खास हमलावर तैयार दिखा रहे हैं। सरकार को हालातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी को सही मायनों में उन्होंने एक अखिल भारतीय मुद्दे में तब्दील कर दिया है। ऐसे में ये यात्रा क्या रांज लाती है। कांग्रेस और बिहार के गवर्नर को विधानसभा चुनाव में कैसे फायदा पहुंचाती है। 80 सीटें वोट चोरी, 48 सीटें वाले महाराष्ट्र और 42 सीटें वाले बंगाल में बीजेपी गिरी। लेकिन 40 सीटें वाले बिहार ने मोदी को बचा लिया। अगला युद्ध उसी बैटल ग्राउंड में है। जहां 90 के दशक के बाद कांग्रेस कोमो ठप नहीं सकी है। राहुल जहां मोदी के साथ सरे लगाने के लिए जरूर हैं वहां की पॉलिटिकल पिक्चर पर थोड़ा नजर डालें तो राहुल गांधी की बिहार यात्रा का महसुद बहुत समज को आकर्षित करना और नतीजा कुमार की जरूरत व चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में संत लांगाना है। राहुल ने जति जगजगन, आलख की सीमा हटाने, अत्याचारों को उजागर करने और समीपवृक्षता को मिलाकर कर नई पहचान गढ़ी है। वो मुकेश सहनी की लोआईया पार्टी और दीपकर भुवार्थी की सीपीआर पार्टी की लाइन पर हैं।

राजनीति में अपने शुरूआती दिनों में भी राहुल ने पश्चिम यूपी के भूटन-पारसीत में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पदयात्रा की थी। उनकी यात्रा को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के लिए एक और चुनौती के रूप में देखा गया था। राज्य सरकार ने युवा संसद को 9 जुलाई को पडोसी अलीगढ़ जिले में किसानों की महापंचायत की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जो जखरन भूमि अधिग्रहण को लेकर इसी तरह के आक्रोश का सामना कर रहे थे। मंदिर में राहुल ने ग्रामीणों से कहा था कि मैंने आज तक एक भी किसान नहीं देखा जो विकास के खिलाफ हो। मगर विकास के नाम पर आपकी जान पर जोरि हो रही है। किसानों के मुँह की आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा की। 30 दिनों के दौरान वह लगभग एक महीने में 2,500 किमील्टर की दूरी तय किया था। राहुल देवरिया के पंचरात्री गांव से अपनी यात्रा की शुरूआत की थी। यात्रा के दौरान पार्टी वर्कर्स घर-घर जाकर घरों के मुखिया से किसानों की समस्याओं के बारे में बर्चा की थी। यात्रा के लिए 250 मिनी थ्रु तैयार किए गए। तब यूपी में कांग्रेस ने नारा दिया था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ...समर्थन मूल्य का करो हटावा।

2015 में उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। इसका महसुद यह बनाता था कि 2013 में आइं आपदा के बाद स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। पैदल करके केदार नाथ मुकेश पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि वहां आकर मुझे आम जैसी शक्ति मिली है। यदि केलव टीवी चैनल को तक कर्वांही सीमित कर दी जाएगी, तो एक बड़ी आबादी लोकतांत्रिक विमर्श से वंचित रह जाएगी। जब केवल चुनिंदा माध्यमों को अनुमति होगी, तो यह संदेश जगजाग कि सूचना पर नियंत्रण किया जा रहा है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होगी। भारत में 82 करोड़ करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। लगभग 45 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) पर सक्रिय हैं। टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है, जबकि मोबाइल पर समाचार देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संसद टीवी और राज्य विधानसभा के चैनल बहुत कम दृश्यकों तक पहुंच पाते हैं, जबकि यूट्यूब पर एक लाख स्ट्रीम लाखों देखें जुटा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लोकतंत्र में डिजिटल पारदर्शिता ही जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है। टीवी चैनल अब भी सीमित वर्ग तक ही पहुंचते हैं, जबकि सोशल मीडिया की पहुंच गांव-गांव और युवाओं तक है। भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहाँ सूचना को केवल टीवी चैनलों तक सीमित करना सम्य की माँग से मेल नहीं खाता। आज की राजनीति और समाज का बड़ा विशिष्ट दिक्कत ट्रेंडस और यूट्यूब डिक्टेट्स में ही आकार लेता है। यह सही है कि सदन की कार्यवाही को असंरक्षित तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाना उचित नहीं। कई बार मन्त्राया या राजनीतिक हमले के लिए हिस्से काटकर वायरल कर दिए जाते हैं। इससे जनता तक अशुभी और गलत तस्वीर पहुंचती है। लेकिन समाधान यह नहीं है पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। बेहतर उपाय यह हो सकता है कि विधानसभा खुद एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल, ट्विटर ट्रेंड और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। वैसे से कार्यवाही का समूर्ण और बिना संशयवाता प्रसारण किया जाए। साथ ही स्पष्ट नियम बनाए जाए कि अन्य लोग इस आधिकारिक कंटेंट को संरंभ बदलकर नहीं इस्तेमाल कर सकते।

है। राहुल ने कहा कि मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ माया नहीं, लेकिन मैंने मंदिर के भीतर गया तो मुझे आम जैसी शक्ति मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये आपदा आई तो जो सही अफसर काम करते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके बारे में काफ़ी नकारात्मक बातें कही गईं लेकिन आपदा आने के बाद से अफसरों ने, सेना ने, पुलिसवालों ने बहुत अच्छा काम किया। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत अलग है वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरा फोकस राहुल गांधी पर था। पूरा भारत अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेता खासकर तेजस्वी यादव बराबरी से शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल पूरी यात्रा के दौरान पैदल चले थे। वोट अधिकार यात्रा में राहुल जीप में रहे और आम लोगों से सीके मिलने नहीं गए। राहुल की यात्रा पेस समय हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि न्यू ड्राफ्ट खोल में जिनके नाम हटाए गए हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। बिहार में इसी साल के आठवें तक विधानसभा चुनाव होंगे हैं और उसके कुछ महीनों पहले जब अचानक से एएसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ताम्राम संदेह उठने लगें। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सामने आए और उनके हथों में आयोग का दिया वोट हरित लिस्ट मीडिया को 2024 पोल डेटा का एक ऑनलाइन प्रजेेंटेशन करके दिखाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कैसे महापक्ष में पांच महीने के अंदर 1 करोड़ न्यू वोटर्स को जोड़ा गया। चुनाव आयोग ने पोल डेटा का सॉफ्ट कॉपी देने से नाच कर दिया। कांग्रेस को पेपर सीके निकालने पड़े। जो पेपर निकला भी वो असीआर और सीपीआर केवरज रमीन से निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि चुनाव आयोग चाहता है कि सीसीडीए यूएन को खर कर दिया जाए। जिससे एक्टा वोटर गायब हो जाए

चुनावी प्रचार सोशल मीडिया पर, तो विधानसभा क्यों नहीं?



— डॉ. प्रियंका सौरभ —

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उन्हीं पारदर्शिता और जनता की भागीदारी में निहित है। संसद और विधानसभाएं जनता की आज्ञा का प्रतिनिधित्व करती हैं और वही स्थान हैं जहाँ नीतियाँ, कानून और जनहित से जुड़े अहम मुद्दे तय किए जाते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही तक जनता की पहुँच किसी भी सभ्य लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत कही जा सकती है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया गया यह निर्णय कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और वेब चैनलों पर अब विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण नहीं किया जाएगा, कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। यह फैसला पारदर्शिता को सीमित करने वाला है या फिर सदन की गरिमा को बचाने वाला? इसी तरह संसदीयता का मूल प्रश्न है।

पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई क्रांति ला दी है। पहले वाले लोग टीवी समाचार चैनलों या अखबारों के भरोसे रहते थे, वहीं अब फेसबुक लाइव, यूट्यूब स्ट्रीमिंग और ट्विटर अपडेट्स से उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाती है। विधानसभा या संसद जैसी संस्थाओं की कार्यवाही अब केवल टीवीवार्ड के भीतर सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे जनता के मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचने लगी। आम नागरिक, खासकर युवा, लोकतांत्रिक विमर्श से जुड़ने लगे। उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि उनके वुने प्रतिनिधि सदन में उनके मुद्दों पर किस तरह की बहस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इसके नकारात्मक पल्लू भी सामने आए।



यदि विधानसभा की कार्यवाही सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है तो फिर नेताओं और दलों को भी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज वोट माँगने के लिए रैलियाँ और टीवी के साथ-साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। ऐसे में केवल सदन की कार्यवाही को रोकना अनुचित प्रतीत होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष संचार के लिए सामान हों, तभी वास्तव में जनता का विश्वास कायम रह सकता है। भारत में 82 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 45 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। टीवी दर्शकों की संख्या घट रही है और लोग मोबाइल पर सीधे समाचार देखना पसंद करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही केवल टीवी चैनलों तक सीमित करने का निर्णय लोकतांत्रिक पारदर्शिता को सीमित कर सकता है। बेहतर उपाय यह होगा कि विधानसभाएं अपने आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएँ, जहाँ कार्यवाही का समूर्ण और सत्य प्रसारण हो। इस तरह सदन की गरिमा भी बनी रहेगी और जनता को सूचना तक पहुँच का अधिकार भी मिलेगा।

कई बार सदन की गंभीर बहस के छोटे-छोटे अंश निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए, जिसका प्रयोग राजनीतिक प्रचार, व्यंज या गलतफहमी फैलाने के लिए किया गया। नतीजतन कार्यवाही का वास्तविक उद्देश्य भी छूट गया और विवादों ने ज्यादा सुर्खियाँ बरसे। हरियाणा प्रदेश विधानसभा अब हर रिवरिड कथ्याण का कनहा है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो—वेडेशों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कई बार असंरक्षित शब्दों, हमलों और कथकों के छोटे-छोटे हिस्सों को बार-बार प्रसारित किया जाता है, जिससे जनता तक केवल नकारात्मक छवि ही पहुँचती है। उन्होंने आरोपें आदि करते हुए स्पष्ट किया है कि अब से केवल माध्यम यात्रा टीवी चैनल ही कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर

सकेंगे, जबकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव या रिकॉर्डिंग डालने पर सख्त प्रतिक्रिया रहेगी। उनका तर्क यह भी है कि सदन की कार्यवाही से हटाए गए शब्दों और अंशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना सदन की गरिमा को उल्लंघन है। इसीलिए इंटर प्रचलन में यह सही कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। हालाँकि यह तर्क तसही तौर पर सही प्रतीत होता है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से कई प्रश्न भी उठते हैं। विधानसभा जनता के देखने से चलती है, और वहाँ की हर गतिविधि का सीधा संबंध नागरिकों से है। ऐसे में सूचना तक पहुँच को सीमित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरित माना जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी टीवी नहीं देखती। वह यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर

सक्रिय है। यदि केलव टीवी चैनल को तक कर्वांही सीमित कर दी जाएगी, तो एक बड़ी आबादी लोकतांत्रिक विमर्श से वंचित रह जाएगी। जब केवल चुनिंदा माध्यमों को अनुमति होगी, तो यह संदेश जगजाग कि सूचना पर नियंत्रण किया जा रहा है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होगी। भारत में 82 करोड़ करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। लगभग 45 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) पर सक्रिय हैं। टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है, जबकि मोबाइल पर समाचार देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संसद टीवी और राज्य विधानसभा के चैनल बहुत कम दृश्यकों तक पहुँच पाते हैं, जबकि यूट्यूब पर एक लाख स्ट्रीम लाखों देखें जुटा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लोकतंत्र में डिजिटल पारदर्शिता ही जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है। टीवी चैनल अब भी सीमित वर्ग तक ही पहुँचते हैं, जबकि सोशल मीडिया की पहुंच गांव-गांव और युवाओं तक है। भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहाँ सूचना को केवल टीवी चैनलों तक सीमित करना सम्य की माँग से मेल नहीं खाता। आज की राजनीति और समाज का बड़ा विशिष्ट दिक्कत ट्रेंडस और यूट्यूब डिक्टेट्स में ही आकार लेता है। यह सही है कि सदन की कार्यवाही को असंरक्षित तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाना उचित नहीं। कई बार मन्त्राया या राजनीतिक हमले के लिए हिस्से काटकर वायरल कर दिए जाते हैं। इससे जनता तक अशुभी और गलत तस्वीर पहुंचती है। लेकिन समाधान यह नहीं है पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। बेहतर उपाय यह हो सकता है कि विधानसभा खुद एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल, ट्विटर ट्रेंड और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। वैसे से कार्यवाही का समूर्ण और बिना संशयवाता प्रसारण किया जाए। साथ ही स्पष्ट नियम बनाए जाए कि अन्य लोग इस आधिकारिक कंटेंट को संरंभ बदलकर नहीं इस्तेमाल कर सकते।

मांसाहारी दूध पर भारत-अमेरिका विवाद



—सुरेश गोयल घूष वाला —
अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 : टीएफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच मीडिया फ्लेमिंग्स (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) पर सक्रिय हैं। टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है, जबकि मोबाइल पर समाचार देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संसद टीवी और राज्य विधानसभा के चैनल बहुत कम दृश्यकों तक पहुँच पाते हैं, जबकि यूट्यूब पर एक लाख स्ट्रीम लाखों देखें जुटा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लोकतंत्र में डिजिटल पारदर्शिता ही जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है। टीवी चैनल अब भी सीमित वर्ग तक ही पहुँचते हैं, जबकि सोशल मीडिया की पहुंच गांव-गांव और युवाओं तक है। भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहाँ सूचना को केवल टीवी चैनलों तक सीमित करना सम्य की माँग से मेल नहीं खाता। आज की राजनीति और समाज का बड़ा विशिष्ट दिक्कत ट्रेंडस और यूट्यूब डिक्टेट्स में ही आकार लेता है। यह सही है कि सदन की कार्यवाही को असंरक्षित तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाना उचित नहीं। कई बार मन्त्राया या राजनीतिक हमले के लिए हिस्से काटकर वायरल कर दिए जाते हैं। इससे जनता तक अशुभी और गलत तस्वीर पहुंचती है। लेकिन समाधान यह नहीं है पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। बेहतर उपाय यह हो सकता है कि विधानसभा खुद एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल, ट्विटर ट्रेंड और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। वैसे से कार्यवाही का समूर्ण और बिना संशयवाता प्रसारण किया जाए। साथ ही स्पष्ट नियम बनाए जाए कि अन्य लोग इस आधिकारिक कंटेंट को संरंभ बदलकर नहीं इस्तेमाल कर सकते।

दुग्ध, हड्डियों को पीसकर बनाया गया बोन मील,मालती से निकले तेल और चूर्न। इस मिश्रण को अन्य अनाज और विटामिन सप्लीमेंट्स के साथ मिलाकर पशु-आहार बनाया जाता है। अमेरिका के रूप में 'सामान्य फार्मिंग प्रैक्टिस' के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि कुछ दृष्टिकोण में यह पोषण बढ़ाने और ट्रैक मैनेजमेंट का एक व्यावहारिक तरीका है। लेकिन भारतीय परंपरा में, यह पूरी प्रक्रिया नैतिक रूप से अनुचित और अस्वीकार्य मान्यताओं के विपरीत मानी जाती है। भारत ने अमेरिका से साफ कहा है कि यह या तो अमेरिकी गावों को मांसाहारी चारा देना बंद करे, या फिर ऐसे दूध और डेयरी उत्पादों को सफेद तबल लगाएँ, जिनसे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। लेकिन अमेरिका का तर्क है कि उनकी कृषि प्रणाली में यह मान्यता प्रक्रिया है और वे इसे बदलने के लिए बाध्य नहीं हैं। अमेरिका का मानना ​​है कि लेबलिंग की ऐसी हदें गैर-जुर्तबी बाजार हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के विपरीत हैं। यह विवाद केवल दूध के आयात-निर्यात का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और व्यावसायिक र्थितों का टकराव है। भारत के लिए यह मामला धार्मिक और नैतिक आस्था से जुड़ा है, जबकि अमेरिका इसे महज व्यापारिक अवसर और कृषि पद्धति का हिस्सा मानता है। बहस कर कि दोनों देशों के बीच डेयरी उत्पादों पर कोई ठोस व्यापारिक समझौता बन सके तो यह हो पाया है। दूध और उससे मधुवी उत्पादों से बची-खुची सामग्री से तैयार होता है। इसमें शामिल होते हैं—मुर्गियों और मछलियों के आंतरिक अंग, हड्डी और रक्त का पाउडर,पशुओं के मांस के बचे हुए

और उस पर सवाल न उठे। कांग्रेस को खूब सीटों के नतीजों पर कांग्रेस जो संकेत जाहती रही है, उसने बल मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, तो माना गया कि राहुल की मेहनत रंग लाई है। इसी से यह संभावना भी टटोली गई कि क्या एक और यात्रा हो सकती है। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए समजावया वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिंडा, दलित, आदिवासी) फॉर्मूला लेकर आई। राहुल के सामाजिक न्याय और आरक्षण बचाव वाले एजेंडे के साथ मिलकर अखिलेश ने काम किया और इसका सीधा फायदा सपा को नजर आया। वैसे ही कुछ राहुल ने मायावती सरकार के दौरान साल 2007 में भ्रष्टाचार के विरुध में अभियान चलाया था। कहा तो ये भी जाता है कि इसका फायदा 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उठाया था। तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक में कांग्रेस के हाथियों पर हलकों के बावजूद सहयोगियों की तरफ से खासरी तयज्यो दी जा रही है। अब बारी बिहार की है और वहां तो पहले से ही इंडियन जीप पर तेजस्वी और राहुल गांधी की सीट पर बैठ राज्य के सिविलीसी समीकरण में कौन लीटर, कौन सहयोगी की भूमिका को साफ कर चुके हैं। राजद का राष्ट्रीय संमंदन ने पोल डेटा का सॉफ्ट कॉपी देने से नाच कर दिया। कांग्रेस को पेपर सीके निकालने पड़े। जो पेपर निकला भी वो असीआर और सीपीआर केवरज रमीन से निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि चुनाव आयोग चाहता है कि सीसीडीए यूएन को खर कर दिया जाए। जिससे एक्टा वोटर गायब हो जाए

राजा भैया का पत्नी वाला ग्रह खराब, कुछ नहीं कर सकते थे तो घर-घर की कहानी है -अक्षय प्रताप



संवाददाता-गोण्डा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोड़ा पहुंचे। उन्होंने सफ़िक हटारस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की समीक्षा की और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कुटुंब परिवार को लेकर कहा कि अगर कुटुंब परिवार नहीं करे तो विवाह और शादी कैसे होगा। कुटुंब की बैठकें नहीं करे तो फिर क्या करे। राजपूत हमेशा सब समाज को साथ लेकर चला है। बुजभूषण ने सही काले हुए खराब हो गया है, तो उनको लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत लोगों का यह खराब होता है, आगका भी हो सकता है, सब आप बचकर रहिए। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अब

तीसरे नंबर की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार हम 20 सीटों पर लड़े और 2 सीट जीते। तीसरे नंबर पर रहने वाला पहला बनने की कोशिश करता है। गठबंधन पर हमारा कुछ नहीं है। हम अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं और किसी पर निर्भर नहीं हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों में हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। पार्टी ने तय किया है कि पंचायत चुनाव भी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। अक्षय प्रताप ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे, दूसरी जाति थोड़ी कलाला सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अखंड पार्टी समाज से आते हैं। कर्म से हमें बिकारी की है। वे पक्षीय से विकार करते हैं और हम राइफल से, यानी वे हमसे भी बहादुर हैं। हर राजा-महाराजा के साथ हर समाज के लोग लड़ें हैं। बुजभूषण शरण सिंह से संबंधों का कहना उन्होंने कहा कि बुजभूषण शरण सिंह उनके बड़े भाई हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। उनके सारे बेटे विधायक और सांसद बन चुके हैं। वहीं, योगी सरकार के कामों को लेकर उन्होंने कहा कि हम उनसे सब कामों से सहमत नहीं हैं। जैसे किसानों को खान नहीं मिल रही है, कृषि चंड महंगे हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को डे से कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने विहार में हो रहे चुनाव और वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल खड़ा किया।

पीआरडी जवान 27 दिन से लापता, बाइक और मोबाइल लावारिस हालत में मिला



संवाददाता-बलरामपुर। पीआरडी का एक जवान रहस्यमय परिस्थितियों में 27 दिन से लापता है। जवान की ड्यूटी सावन माह में झारखंडी महादेव मंदिर पर लगाई गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उनको तब पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। यह पूरा मामला ललिया थाना क्षेत्र के रामदासलाही गांव निवासी सुमित्रानाथ मिश्र का है। वे बीते 29 जुलाई से लापता हैं। परिजनों के अनुसार, वह प्रतिदिन करीब 25 किमी दूर जाकर ड्यूटी करते थे। घटना की रात वह घर से ड्यूटी के लिए निकले लेकिन लौटकर नहीं आए। स्थिति परिजनों ने तत्काल शुरू की तो उनकी बाइक (सूफी4, एटी 0624) और मोबाइल फोन गनवरिया स्थित राममितन दास मंदिर समाधि स्थल पर लावारिस

हालत में मिले। इसके बाद परिवार का शक और गहरा गया। बता दें कि लापता पीआरडी जवान मुक्ति नाथ मिश्र के परिवार में पत्नी फूलमती की एक बेटा और दो बेटे हैं। परिवार का भरण-पोषण उनकी ड्यूटी से मिलती वही वेतन पर संतो होता है। बेटों की शादी के लिए रिश्ता तलाश जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। परिजनों का कहना है कि घटना का कथित एक महिला होने वाला है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। परिवार प्रश्नान से जल्द से जल्द उनके पिता को ढूँढने की गुहार लगा रहा है। परिजनों की तहरीर पर नगर कोतवाली ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस को कोतवाली प्रामी सुधीर सिंह ने बताया कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

तोताद्रिमठ में हुआ सामूहिक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ



—भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या की पावन तिथि पर रामायण सुमिरा की प्रतिष्ठित पीठ उत्तर तोताद्रिमठ विभीषणकुंड अयोध्या धाम में संत-धर्मचार्यों के द्वारा सायंकाल सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह आयोजन धर्म शांति के तत्वाधान में आयोजित रहा। जो उत्तर तोताद्रिमठ के वर्तमान पीठाधिकारी श्रीमच्छातुंग रामानुजाचार्य स्वामी अन्तावर्ष के कुशल सांनिध्य एवं बालन मंदिर पीठाधीश्वर महंत वेदहीवल्लभ शरण की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक कोशल जी मौजूद रहे। सर्वप्रथम बलरामचंदी के शिष्य पर पूजन-अर्चन और दीपा प्रज्वलन संग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद संत-महंत, धर्मचार्यों,

वेदपाठी छात्रों, उपस्थित जनों ने सामूहिक सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ के समापन उपरान्त बजरंगशरण महंत आरती उतारी गई। फिर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर तोताद्रिमठ द्वारा संवाचित बालरक्षक सोपान ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी केशव प्रमाणचार्य उपनाम केशव नारायण दूध ने आए हुए संत-महंत, धर्मचार्यों व विभिन्नजनों को अंगवस्त्र ओढ़कर स्वागत-सम्मान किया। तोताद्रिमठ पीठाधिकार स्वामी अन्तावर्ष महाराज ने कहा कि आज हम सब एक मंच पर एकत्रित होकर भगवान श्रीराम-बजरंगवली के मंत्रिका की गाथा सुन रहे हैं। यह हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही सौभाग्य एवं गर्व का विषय है। महंत वेदहीवल्लभ शरण ने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है। जिस संप्रदायियों में प्रथम पुरी भी कहा

केंद्रीय मंत्री ने महाराजगंज के विकास कार्यों का लिया जायजा



‘संवाददाता-महाराजगंज। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने रविवार को पतियारा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने परतावल, श्यामदेउवा, रामपुर, पतियारा, गंगी और मुजुरी में ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने मोदी-योगी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, महिला और नौजवान की सरकार है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि इसके प्रमाण हैं। पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए आरोप मेले में 46 मरीजों को मिला मुफ्त इलाज और दवाएं ‘संवाददाता-महाराजगंज। चौक सांमुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित आरोप मेले में 46 मरीजों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे। चिकित्सक डॉ. रामस्वरूप ने भी मुफ्त इलाज और दवाएं प्रदान की। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी वितरित

चांदी की पायल, नगदी और मोटरसाइकिल समेत दो आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता-श्रावस्ती। नवीन मॉडर्न पुलिस ने चोरी की वारंता का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। एसपी घनश्याम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दरअसल, थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती के प्रमारी निरीक्षक मणु सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लालबोड़ी में बलरामपुर बॉर्डर के पास से रवीन्द्र पाण्डेय और रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया। रवीन्द्र पाण्डेय इकोना थाना क्षेत्र के रम्पापुर डकाही का रहने वाला है। रोहित वर्मा मलपुरवा अमारे भरिया का निवासी है।

चांदी की पायल, नगदी और मोटरसाइकिल समेत दो आरोपी गिरफ्तार



घटना 15-16 अगस्त की रात की है। चोरी ने हलीमपुरवा चीनपुर की एक महिला के घर की पिछली दीवार से आंगन में प्रवेश किया। करने का दरवाजा तोड़कर बरसे एक ओपों मोबाइल बरामद किया। रोहित वर्मा से दो की-चैड मोबाइल, एक वीबो एंड्रॉइड मोबाइल, 2000 रुपए नगद और एक जेडी बांदी की पायल बरामद हुई। उसके अलावा एक काली

किसानों की आया बढ़ाने के लिए कैंस क्रॉप और एगो प्रोसेसिंग पर जोर



संवाददाता-देवरिया। रविवार को जिला पंचायत समितार में विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए अग्रत प्रयास कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य विषय कैंस क्रॉप और एगो प्रोसेसिंग में प्रोत्साहन था। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और सदर प्रदेश शाखा मणि ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सदर विधायक डा. शलन मिश्र, निपाटी, तमकुली विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अग्रत प्रयास के तहत संकल्प किसानों

तेंदुए को पकड़ने के लिए तलाश जारी, सोतिया गांव में मिले पगचिन्ह, वन विभाग की टीम 24 घंटे कर रही निगरानी



संवाददाता-गोण्डा। खोडार थाना क्षेत्र के सोतिया गांव में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है। देर शाम वन विभाग के एएसडी सुदर्शन कुमार के नेतृत्व में तेंदुए को पकड़ने के लिए सफ़ अमिया चलाकर के तेंदुए की तलाश की गई। वन विभाग की टीम भी पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में कांविन कर रही है। सोतिया गांव के आसपास कई स्थानों पर तेंदुए के पगचिन्ह मिले हैं। वन विभाग की टीम पगचिन्ह के आधार पर तेंदुए की तलाश कर रही है। ज़ोन कैंपरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। वन विभाग के एएसडी सुदर्शन कुमार ने बताया कि चार-पांच दिन पहले जंगली जानवर के आने की सूचना मिली थी। सांठल्लाह नगर रोज के कर्मचारी शिपट में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जंगली जानवर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों और जंगली जानवर की संख्या के लिए पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग को ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्रामीणों को अकेले न जाने और समूह में रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग जानवर को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह तेंदुए है या कोई अन्य जंगली जानवर। वहीं, सोतिया गांव के रहने वाले मधु, सिंह राम,कनिन के बताया कि 6 दिन पहले यहां पर तेंदुआ आया है। उन्होंने कहा-यम लोगों ने खुद अपनी आंख से देखा है, लेकिन वन विभाग मानने को तैयार नहीं है। रात भर हम लोग जाकर के अपने

नहीं रहे अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा पप्पू भैया



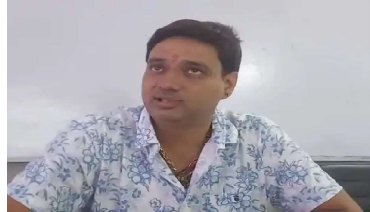
—भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। 74 साल की उम्र में अयोध्या के राजा श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का स्वर्गवास उनके आवास शरण सदन में शनिवार की राति में हो गया, कुछ दिन पहले उनका स्वाइन का ऑपरेशन हुआ था और तीन दिन पहले वह लखनऊ से चेकअप कर के लौटे थे रात्रि में आचानक तबियत बिगड़ी श्री राम हॉस्पिटल के डॉक्टर राज सदन पहुंचे और वहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। सुप्रिी कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने जब मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को गठन किया तो उसमें अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का भी नाम था और वह पूरी तन्मयता के साथ मंदिर निर्माण के साथ प्राण तिष्ठता के भी साक्षी बने उनका अंतिम संस्कार राज्य परिवार की तरह किया गया जिसमें अयोध्या के संत महंत गृहस्थ राजनेता अयोध्या के लोग भारी संख्या में सम्मिलित हुए और अंतिम विदाई दी। राज परिवार की तरफ से अयोध्या में महाराजा इंटर कॉलेज राज एक समारंभ शिक्षा का उत्तम केंद्र माना जाता था और आज भी वह अयोध्या के लिए एक अलग केंद्र विद्यालयों के लिए एक अलग केंद्र थापित है और यहां दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी के साथ-साथ महाराजा पब्लिक स्कूल और अनेक सामाजिक संस्थानों में पप्पू भैया का नाम बड़े आदर के साथ अतिथि जाता है। अयोध्या में राजस्व परिवार के मौजूदा राज के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या के लोगों के बीच राजा साहब के रूप में जाने जाते थे। वह अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी थे। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और राजनेतों से उनके नजदीकी संबंध रहे। उनके पुत्र यश्वि मोहन प्रताप मिश्र प्रख्यात कवि और लेखक हैं। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर पर उनके अत्यंत गहन प्रेम और अलग-अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाता है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के थे ट्रस्टी, पूरे अयोध्या में शोक की लहर



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के थे ट्रस्टी, पूरे अयोध्या में शोक की लहर मिरजद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी भी जाताया दुख, भगवान और अल्लाह से की दुआ, भगवान और अल्लाह रहे अपने चरणों में स्थान दें। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपन राय सपा के पूर्व महागनार अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, कमिश्नर, आईटी, डीएम एसएसपी ने भी राज सदन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुप्रिी कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के राजा लाल देव गई सब लोग रामजन पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की राज परिवार को डांडस बढ़ाया। अयोध्या के संत महंत वरिष्ठ नामिक राजनेता राज सदन पहुंचे और भी पुष्पांजलि अर्पित की। धर्म सनातन महंत ज्ञान रामलाल टेट से निकल कर अखाई मंदिर में जागरे और जिस बांदी के महासंघ पर प्रभु श्री राम लाल अपने संजय दास राज सदन पहुंचे पप्पू भैया को पुष्पांजलि अर्पित की उनके परिवार से मुलाकात की इस दौरान कुशनामिक के वरिष्ठ पुनवरी श्रृंगी शिष्य आश्रम के महंत हरेन दास, शिवम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ पर पूज्य दास महाराज राज सदन पहुंचकर के पुष्पांजलि अर्पित की। सप्ता संसांद अयोध्या प्रयास ने कहा वे केवल नाम के राजा नहीं थे वह दिल के भी राजा थे, उनके निधन से दिल दुखी है। बावरी

11 कन्याओं की पढ़ाई, शादी का खर्च उठाएगा युवा सोच संगठन



संवाददाता-गोण्डा। युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह मदीरिया ने कजरी तीज पर एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की है। वे इस त्योहार पर 11 कन्याओं को गौद लेंगे। इन कन्याओं की शिक्षा से लेकर विवाह तक का सारा खर्च वे वहन करेंगे। अनिल सिंह पहले से ही समाज सेवा में सक्रिय हैं। वे रोज शाम को गांधी के गुरु नानक चौदावें अंशक बैरवाह, बड़गांव चौधौल और गांधी ट्रेडिंग पर जबरनरत लोगों को भोजन वितरित करते हैं। सदियों में गरीबों को भुगत कपड़े देते हैं। दीपावली पर 50 से अधिक गरीब परिवारों को त्योहार मनाने का सामान उपलब्ध कराते हैं। अनिल सिंह ने बताया कि वे हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन और कजरी तीज पर कुछ विशेष करते हैं। इस बार गौद दी गई कन्याओं को ऐसी शिक्षा दिलाएंगे, जिससे वे अच्छी नौकरी पा सकें। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद भी इन कन्याओं को कोई समस्या होगी, तो वे उसका समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा अपने पिता और पत्नी से मिली है। उनकी पत्नी अमर-समय पर उन्हें मार्गदर्शन देती रहती हैं। उनका मानना है कि इस तरह की समाज सेवा से लाभार्थी अजीबान कृतज्ञ रहते हैं। अनिल सिंह मदीरिया ने कहा कि आज कहीं भी मुझे बेटी की मिलाती है किसी गरीब बेटी की शादी है वहां भी मेरे दाद-बड़-चढ़कर उसकी मदद की जाती है। गरीब बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, अपना आत्म जाकर के बच्चों के साथ मेरे द्वारा अलग-अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाता है।

dainikbhartiyabasti@gmail.com

द० हाकिम